उत्तराखंड उच्च न्यायालय

25 जनवरी, 2021 को परमजीत सिंह सागर बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

(निर्णय सुरक्षित)

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

2018 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 125

परमजीत सिंह सागर .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

वर्तमान: श्री वीके कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कांति राम शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त,
आवेदक के लिए वकील.
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप. सुश्री शिवांगी गंगवार के साथ एजी, संक्षिप्त
राज्य के लिए धारक.
श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ललित शर्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई।
निजी प्रतिवादी के लिए वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विवेचक/पति द्वारा 2017 के शिकायत वाद संख्या 1141 "श्रीमती नीतू बनाम परमजीत" में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.03.2018 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम की धारा 23(2) के तहत निचली अदालत, 2005 ने पति/संशोधक को पत्नी/प्रतिवादी नंबर 2 को 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है। दिनांक 23.03.2018 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता/पति ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 53/2018 में अपील दायर की, जिसे भी आदेश दिनांक 27.04.2018 और आदेश दिनांक 23.03.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित की पुष्टि की गई। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण।

2. संशोधनवादी/पति और प्रतिवादी नंबर 2 - श्रीमती नीतू कैंथ का विवाह वर्ष 2004 में संपन्न हुआ था। प्रतिवादी संख्या 2 ने महिलाओं की सुरक्षा की धारा 23(2) के तहत पति/संशोधनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 13 वर्ष की अवधि के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम , 2005। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 23.03.2018 के आदेश के तहत पति/पुनरीक्षणकर्ता को पत्नी/प्रतिवादी नंबर 2 को 15,000/- रुपये (केवल पंद्रह हजार रुपये) का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 23.03.2018 का आक्षेपित आदेश प्रतिवादी संख्या 2/पत्नी द्वारा इस आधार पर प्राप्त किया गया है कि न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, देहरादून ने प्रतिवादी संख्या 2/पत्नी को पुत्र अर्थात् परनीत को पेश करने का निर्देश दिया था। सिंह सागर, ताकि पक्षकारों को बेटे से मिलने की अनुमति दी जा सके। जहां तक, नीचे दिए गए न्यायालय के निर्देशों का संबंध है कि पुनरीक्षणकर्ता/पति प्रतिवादी संख्या 2/पत्नी पर कोई घरेलू हिंसा नहीं करेगा, यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2/पत्नी पुनरीक्षणकर्ता के साथ नहीं रह रही है। जहां तक शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 और उसके बेटे के पासपोर्ट सौंपने के निर्देश का सवाल है, इसे विपरीत पक्ष को अवसर दिए बिना एकपक्षीय पारित नहीं किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या प्रतिवादी का पासपोर्ट क्रमांक.

4. यह भी रिकॉर्ड में आया है कि संबंधित मामलों में प्रतिवादी नंबर 2/पत्नी और उसके बेटे को दिनांक 06.04.2019 के आदेश के मद्देनजर अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 18,000/- रुपये (अट्ठारह हजार रुपये मात्र) मिल रहे हैं।

5. विद्वान मजिस्ट्रेट के पास पुनरीक्षणकर्ता/पति को प्रतिवादी संख्या 2/पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का भुगतान करने का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था।

6. चूंकि, प्रतिवादी क्रमांक 2/पत्नी और उसके बेटे को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में अंतरिम भरण-पोषण मिल रहा है , इसलिए धारा 23(2) के तहत प्रतिवादी क्रमांक 2/पत्नी को भरण-पोषण देने का कोई प्रावधान नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय से मामले में हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

8. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। दिनांक 23.03.2018 और 27.04.2018 के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है A पुनरीक्षणकर्ता/पति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून को वापस भेज दिया गया है।

(लोकपाल सिंह, जे.) 25.01.2021